अपेक्षाकृत कम भाव पर ब्राजील से भारत में आधारित चीनी का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने सरकारी खाते में जुलाई से दिसंबर 1994 के दौरान 9.77 लाख टन चीनी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति के लिए आयात किया। यह पूरी मात्रा रिफाइंड शुगर एसोशियसन (आ० एस० ए०), लन्दन के सदस्यों के साथ अनुबन्धित की गई। जहां तक "इकोनोमिक टाइम्स" जो 14 जुलाई, 1995 को प्रकाशित हुआ में छपी रिपोर्ट का संबंध है, ऐसा लगता है कि गैर आर० एस० ए० आपूर्तिकर्ता के साथ आर०एस०ए० आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए अनुबंध की तुलना की गई है। एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० को आर० एस० ए० सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों से कहीं अधिक सस्ते मूल्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर आर० एस० ए० सदस्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्रस्तावों के साथ पेश की गई कीमत के 5% के बंधपत्र (बाईड बांड्स) देने अपेक्षित थे। एस० टी० सी० ने सूचित किया है कि केवल दो गैर आर० एस० ए० पार्टियों ने ऑफर भेजने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर बंधपत्र (बाईड बांड्स) जमा कराने का प्रस्ताव रखा। इन पार्टियों को एक-एक करके आदेश दिए गए। तथापि, एक पार्टी ने निर्धारित बाईड बांड् नहीं जमा कराए तथा दूसरी भी कार्य पूरा न कर सकी।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम० एम०टी० सी०) ने भी इस तरह की तीन पार्टियों को आदेश दिए जिन्होंने आर० एस० ए० सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यों की तुलना में कम मूल्य पर बंध पत्र (बाईड बांड्स) के साथ अपने वैध प्रस्ताव जमा कराए लेकिन इसी प्रकार से ये पार्टियां भी अनुबंध पूरा नहीं कर सकीं। एम० एम० टी० सी० तथा एस० टी० सी० ने पुष्टि की कि अक्टूबर, 1994 में मद्रास में इकोनामिक टाइम्स में जैसा प्रकाशित हुआ था कि उनका मैसर्स पैरिस की सकडैन कैरी के साथ 14000 टन ब्राजीलियन चीनी का अनुबंध किया है। वाणिज्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने जिन मूल्यों पर आयात किया है वे दूसरे भारतीय आयातकों के आयात मूल्यों के बराबर ही हैं।

Import of COCOA Beans

739. **SHRI V. GOPALSAMY**: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of cocoa beans imported during the last three years, year-wise;

(b) what has been the domestic production of cocoa during this period;

(c) whether there was any gap between production and demand during this period;

(d) out of the imports, how much has been made by major multinationals, year-wise figures;

(e) whether it is a fact that Government have permitted the multinationals to import more than required to the disadvantage of farmers; and

(f) whether Government propose to curtail import of cocoa beans, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Item 'Cocoa Beans' as such is not classified in the ITC(HS). However import of cocoa beans during the last three years had been as under:—

Year	*Quantity (Tons)*
1992-93	1243
1993-94	220
1994-95	706

Source: DGCI&S CALCUTTA.

(b) and (c) Firm production estimates of cocoa beans are available only upto 1992-93. The year-wise production of cocoa beans during the years 1990-91, 1991-92 & 1992-93 had been 6946, 7376 & 6821 tonnes respectively. While available information indicates that 1993-94 was a normal year for cocoa

production, incidence of some disease was reported in 1994-95 which may have affected production to some extent.

As per Indian Confectionary Manufacturer's Association the requirement of cocoa beans for domestic chocolate and cocoa is of the order of 7000 to 7500 tonnes.

(d) Company-wise data on imports are not maintained.

(e) No, Sir.

(f) Cocoa is already covered under the Negative List of Imports.

Reduction of export targets from Kandla zone by MMTC and STC

740. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the export targets from Kandla export free trade zone, especially of minerals, garments and other commodities have been reduced by MMTC and STC over the years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the imports through Kandla export free trade zone during each of the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) STC and MMTC do not have any export targets from Kandla Free Trade Zone since they do not have any production units there.

(c) Details of imports in Kandla Free Trade Zone for the last three years are as under:

Year	*Imports (Rs. in Crores)*
1992-93	72.29
1993-94	86.21
1994-95	184.00

सुपर बाजार में महिला कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें

741. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनेक सांसदों से सुपर बाजार के वस्त्र विभाग में तैनात पुरुष कर्मियों द्वारा महिला बिक्री सहायकों के जातीय उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कुछ कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार के कुछ अधिकारियों, विशेषकर कार्मिक और वस्त्र विभाग के प्रबंधक, द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है;

(घ) क्या सुपर बाजार के दूरदराज स्थित शाखाओं में तैनात महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लग गया है; और

(ङ) क्या किसी महिला बिक्री सहायक ने सांसदों के पास अपनी पर्याप्त सुरक्षा और अपने साथी पुरुष कर्मचारियों से बचाव के संबंध में कोई शिकायत भेजी है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री बिनोद शर्मा): (क) जी नहीं। इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आठवीं योजना अवधि के दौरान सुपर बाजार द्वारा सृजित रोजगार

742. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक सुपर बाजार ने अनुमानतः कितने अतिरिक्त रोजगारों का सृजन किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक श्रमिकों की संख्या में अनुमानतः कितने अतिरिक्त व्यक्ति और शामिल हुए;